

मुकदमों का विवरण

किशोर बालकृष्ण नंद बनाम।

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. (2011 की आपराधिक अपील संख्या 2291) 02 अगस्त, 2023

[जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:कानूनी प्राधिकारी-उप-मंडल मजिस्ट्रेट को संबोधित सद्भावना से शिकायत में लगाए गए आरोप, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि का कारण बनते हैं या नहीं।

दंड संहिता, **1860 -s.499**, आठवाँ अपवाद, धारा **500**-आरोप को सद्भावना से प्राथमिकता दी जाती है-जब मानहानि नहीं होती है:

आयोजित किया गया:आरोप के विषय के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सद्भावना से दायर की गई शिकायत में कानूनी अधिकार वाले व्यक्ति पर आरोप लगाना मानहानि नहीं है-शिकायत में लगाए गए आरोपों पर विचार करने से मानहानि का कोई मामला नहीं बनता है-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है-मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी करने वाले मूल आदेश को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।[पैरा 16 और 17]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2011 की आपराधिक अपील संख्या 2291।

2009 के सी. आर. एल. डब्ल्यू. पी. सं. 676 में नागपुर में बंबई उच्च न्यायालय के दिनांकित 03.02.2010 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

सत्यजीत ए देसाई, अंशुमन अशोक, सिद्धार्थ गौतम, अभिनव के. मुत्यालवार, गजानन एन. तीर्थकर, विजय राज सिंह चौहान, सुश्री अनघा एस. देसाई, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

34

35

किशोर बालकृष्ण नंद बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, भारत बागला, सौरव सिंह, आदित्य कृष्ण, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के आदेश का निर्णय/आदेश

1. प्रत्यर्थी संख्या 2 (मूल शिकायतकर्ता) को हालांकि इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिया गया है, फिर भी उसने व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं रहने और इस अपील का विरोध करने का फैसला किया है। 2. यह भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (संक्षेप में, "आई. पी. सी.") के अंतर्गत दंडनीय मानहानि के लिए बुलाए गए मूल अभियुक्त के आग्रह पर एक अपील है और बॉम्बे, नागपुर पीठ में उच्च न्यायालय द्वारा 2009 की आपराधिक रिट याचिका में पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-किशोर बालकृष्ण नंद के नेतृत्व में रिट याचिका को खारिज कर दिया और इस तरह मजिस्ट्रेट द्वारा मानहानि के लिए प्रक्रिया जारी करने के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया।

3. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने उप-मंडल मजिस्ट्रेट (संक्षेप में, "एस. डी. एम.") को संबोधित लिखित शिकायत दर्ज कराई जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी नं. 2 इसमें (मूल शिकायतकर्ता) ने कुछ भूमि पर अतिक्रमण करके एक दुकान लगाई थी। शिकायत में कहा जाता है कि अपीलार्थी ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाई गई ऐसी दुकान उपद्रव पैदा कर रही थी, क्योंकि कई असामाजिक तत्वों और रोड रोमियो ने उक्त दुकान पर आना शुरू कर दिया था और सभी प्रकार की समस्याएं पैदा कर रहे थे।

4. एस. डी. एम. ने अपीलार्थी के नेतृत्व में दिनांक 25.01.2002 एफ. आई. की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। जबकि एस. डी. एम. के समक्ष कार्यवाही लंबित थी, शिकायतकर्ता ने मानहानि के अपराध के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, वरोरा, चंद्रपुर, महाराष्ट्र राज्य के न्यायालय में एक निजी शिकायत दर्ज करने के बारे में सोचा। विद्वान मजिस्ट्रेट ने उक्त शिकायत पर संज्ञान लिया और प्रक्रिया जारी की। मानहानि के अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा उन कथनों के आधार पर संज्ञान लिया गया था जो अपीलार्थी द्वारा एस. डी. एम. को संबोधित अपनी लिखित शिकायत में किए गए थे, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।

36

/

[2023] 11 एस सी आर।

5. जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है, इसके बाद अपीलार्थी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना के साथ एक आवेदन दायर किया कि प्रक्रिया जारी करने के आदेश को वापस लिया जाए। संबंधित मजिस्ट्रेट ने आदेश को वापस ले लिया। मजिस्ट्रेट द्वारा वापस बुलाए जाने के इस तरह के आदेश से पीड़ित शिकायतकर्ता ने सत्र न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन दायर करके इसे चुनौती दी। पुनरीक्षण आवेदन को अनुज्ञात गई और प्रक्रिया जारी करने के आदेश को वापस लेने के आदेश को रद्द कर दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष गया। उच्च न्यायालय में, अपीलार्थी ने सोचा कि वह अपनी याचिका पर दबाव नहीं डालेगा और उसे वापस ले लिया।

6. आठ साल बाद अपीलार्थी ने प्रक्रिया जारी करने के मूल आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के बारे में सोचा। उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, केवल देरी के आधार पर ऐसी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

7. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

8. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अंशुमन अशोक ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने एक शिकायत पर संज्ञान लेने में गंभीर त्रुटि की है, जो किसी भी अपराध का खुलासा करने में विफल रहती है। उनके अनुसार, भले ही शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया पूरा मामला स्वीकार किया जाता है या माना जाता है कि यह सच है, लेकिन भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि का उल्लंघन करने वाले और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 500 के अंतर्गत दंडनीय बनाए जाने वाले किसी भी तत्व का खुलासा नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किल (अपीलार्थी) ने सद्भावना से एस. डी. एम. के ध्यान में लाया कि शिकायतकर्ता ने भूमि के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण किया था और एक दुकान लगाई थी जो उपद्रव पैदा कर रही थी। विद्वान वकील के अनुसार, यह मानहानि का कोई कारण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अन्यथा भी कथित मानहानिकारक शब्द या बयान एस. डी. एम. जैसे सार्वजनिक प्राधिकरण को संबोधित लिखित शिकायत में दिए गए हैं और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए यह भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 499 की कठोरता को आकर्षित नहीं करेगा।

9. उपरोक्त परिस्थितियों में, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुज्ञात जाए और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।

10. हमने राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री आदित्य अनिरुद्ध पांडे को भी सुना। हालांकि, यह एक निजी शिकायत का मामला है।³⁷.

किशोर बालकृष्ण नंद बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

राज्य की शायद ही कोई भूमिका हो। फिर भी वकील ने विधि के प्रश्न पर हमारी मदद की।

विश्लेषण:

11. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र प्रश्न जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या एस. डी. एम. को संबोधित शिकायत में लगाए गए आरोप भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 500 के अंतर्गत अपराध बनाते हैं या नहीं?

12. भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 499 इस प्रकार है:

“499. मानहानि।—जो कोई भी, बोले गए या पढ़ने के इरादे वाले शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा, किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण होने के संबंध में कोई आरोप लगाता है या प्रकाशित करता है कि इस तरह के आरोप से नुकसान होगा, तो ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इसके बाद के मामलों को छोड़कर, उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए कहा जाता है। ”

13. धारा 499 का आठवाँ अपवाद, जिस पर विद्वान वकील द्वारा निर्भरता रखी गई है, निम्नानुसार है:

“आठवाँ अपवाद।—अधिकृत व्यक्ति की तुलना में अच्छे विश्वास में आरोप को प्राथमिकता दी जाती है।—आरोप के विषय के संबंध में उस व्यक्ति पर वैध अधिकार रखने वालों में से किसी के बजाय किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सद्भावना से आरोप लगाना मानहानि नहीं है। ”14. भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 52 में "सद्भावना" शब्द का अर्थ परिभाषित किया गया है:

“52. ‘अच्छा विश्वास’।—कहा जाता है कि 'सद्भावना' में कुछ भी नहीं किया जाता है या विश्वास नहीं किया जाता है जो उचित देखभाल और ध्यान के बिना किया जाता है या विश्वास किया जाता है। ”15. हमारा विचार है कि कथित अपराध के लिए अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। इस तरह की कोई मानहानि नहीं है।16. धारा 499 का अपवाद 8 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आरोप के विषय के संबंध में उस व्यक्ति पर वैध अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सद्भावना से आरोप लगाना मानहानि नहीं है। यहाँ तक कि अन्यथा अवलोकन करके भी

/

/

[2023] 11 एस सी आर।

शिकायत में लगाए गए आरोपों से हम संतुष्ट हैं कि मानहानि का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

17. मामले के समग्र दृष्टिकोण में, हम आश्चर्य हैं कि अपील को अनुज्ञात जानी चाहिए और इसके द्वारा इसकी अनुज्ञात जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। उसी के परिणामस्वरूप, समन जारी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पारित मूल आदेश को भी रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वरोरा, चंद्रपुर, महाराष्ट्र के न्यायालय में 2002 के आपराधिक मामले के रूप में लंबित आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई है।

18. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील अनुज्ञात ।

निधि जैन

